विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश

अब एक्सप्रेस प्रदेश के नाम से जाना जा रहा उत्तर प्रदेश

इन क्षेत्रों में देश में अव्वल प्रदेश

- उज्ज्वला योजना विद्युत उज्ज्वला विधि योजना के क्रियान्वयन में देश में सर्वाधिक प्रदाहित।
- पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान।
- हरित स्थानों विकास अवार्ड-2020 में राज्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार।
- गन्ना, चीनी, इथेनॉल, एवं टेक्नोलाजर उत्पादन में लगातार दोनों बार देश में प्रथम।
- 1.44 लाख करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान कर देश में अग्रणी
- खाद्यान्न, गेहूं, धान, दाली मटर, आम, अरहर और दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर एक।
- सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 41 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर देश में प्रथम।
- 42 लाख से अधिक प्रवासमजदूरों उत्पादों (सामीण एवं शहरी) का विस्थापन कर देश में अग्रणी।
- उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 67 लाख गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर देश में अग्रणी।
- 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तियों प्रधानमंत्री (उज्ज्वल घर) का निर्माण कर देश में प्रथम
- 24 करोड़ 40 लाख पौधरोपण का रिकॉर्ड।
- सर्वाधिक मोटरवाहन उत्पन्न एवं टैक्सपाता बनने वाला राज्य।
- मोटरवाहन क्षेत्र में सर्वाधिक निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाँक बनने वाला राज्य।
- सर्वाधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने वाला प्रदेश
- चार नए एक्सप्रेस-वे का एक साथ निर्माण कार्य कर देश में प्रथमों।
- 24 जनवरी में महामना एम मोहनलाल कनेक्टिव डिवाइसेस लाख 16 जनवरी में पीपीपी मोडल पर मोबाइल कनेक्टिव की स्थापना की घोषित शुरुआत।
- विमान उपयोग में देश में प्रथम स्थान।

नोएडा में एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी

नोएडा में एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के लिए कार्य प्रारम्भ

इन्वेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से 5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण पूरा, शीघ्र ही वाहनों के लिए खोला जाएगा

5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट

8 एयरपोर्ट, 7 हवाई पट्टियों का किया गया विकास

594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में

अमरनाथ सिंह

लखनऊ। अब राज्य प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। सोमवार से लखनऊ पूर्वांचल हो जाएगा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरोसिटी सहित 7 हवाई पट्टियों का विकास हो चुका है। निर्माण के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को शीघ्र ही वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिली है।

एक्सप्रेस-वे के निर्माण से प्रदेश लखनऊ से बलिया तक दौड़ेगा। 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया गया नहीं, 231 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इस एक्सप्रेस-वे से लखनऊ, हरदोई, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले जुड़ेंगे।

सरकार के कार्यकाल में 14471 किमी सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, 349274 किमी सड़कों को गड्ढा मुक्त और 15246 किमी नई सड़कों व 925 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है।

124 दीर्घ सेतु, 54 रेल उपरिगामी सेतुओं का पूर्ण मार्ग पूर्ण और 300 लघु सेतुओं का निर्माण प्रगति पर है। लखनऊ सुल्तानपुर और मिर्जापुर खंड पुलवारों को दो लेन सड़कों से जोड़ने का काम भी तेज है।

प्रदेश से जुड़ने वाले अन्य राज्यों व देश की सीमाओं तक जाने वाली 82 सड़कों के लिए 1759 करोड़ रुपये की लागत से 929 किमी लंबाई में कार्य प्रगति पर है।

हर घर बिजली का सपना साकार

बिजली उत्पादन बढ़ाने, वितरण व ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने पर रहा सरकार का फोकस, सभी सेवाएं ऑनलाइन होने से उपभोक्ताओं को नहीं लगाने पड़ते दफ्तर के चक्कर

संकेत मिश्रा

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई अहम फैसले लिए। परिणाम यह रहा कि आज प्रदेश में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध है। यही नहीं, प्रदेश के कोने-कोने तक बिजली पहुंचाने का सपना साकार हुआ है। सोनी की मुख्यमंत्री बिजली आपूर्ति के लिए जहां बिजली उत्पादन बढ़ाने, वितरण व ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने पर फोकस रहा वहीं उपभोक्ताओं को सुगम से देशभर में भी बड़ा अहम बदलाव हुआ है। इसके चलते उपभोक्ताओं को अब लगातार बिजली आपूर्ति मिल रही है।

एक कनेक्शन होने, खराब मीटर बदलने, बिजली का बिल ठीक कराने, लोड बढ़ाने या कम कराने, नाम बदले में सुधार, नामांतरण, नई परियोजना, लाइनों विस्तीकरण आदि के लिए उपभोक्ताओं को अब बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ये सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। पिछले साढ़े चार साल में सरकार का जोर इस बात पर रहा है कि जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। इसके लिए सरकारने अभियान चलाकर काम कराया गया। नतीजा यह है कि आज हर गांव, हर घर में या तो सीधे बिजली पहुंच रही है।

चुनिंदा नहीं, हर जिले को बिजली

प्रदेश में पावर सरप्लस करने के बाद अब प्रदेश के चुनिंदा जिलों को ही 24 घंटे बिजली मिलती थी। योगी सरकार ने बिजली आपूर्ति के कोटा को समान करते हुए सभी जिलों मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराई है। सहारे और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के घर बिजली कनेक्शन नहीं थे। योगी सरकार ने दीनदयाल योजना के तहत 1.41 करोड़ घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए हैं। यूपी प्रदेश में उत्पादन क्षेमता के अंतर्गत 2,60,81,000 मेगावॉट का निर्माण किया गया है। लोगों को मुख्यमंत्रुपात बिजली देने के लिए यूपी प्रदेश में 33 केवी से लेकर 765 केवी लाइन तक के जाल बिछाए गए। उपकेंद्रों तथा लाइनों का मेंटनेंस कराकर बिजली बराबर मिल रही है। कई जिलों और उपकेंद्रों में लाइनों का विस्तार किया गया है।

अब ट्रांसफार्मर बदलने में नहीं लगता समय

पहले यहां ट्रांसफार्मर खराब होने पर कनेक्शन होने पर 15 दिन लगते थे। अब नई व्यवस्था में ट्रांसफार्मर खराब होने के 24 घंटे के अन्दर बदल दिये जा रहे हैं। इसके उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला है। किसी दिक्कत के चलते 24 घंटे में नहीं बदल पाते हैं तो उपभोक्ता को मुआवजा भी दिया जाता है।

- आपूर्ति संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत हुई है।
- किसानों और गांवों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार किसानों सरकारों को लगभग 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे चुकी है। सुनिश्चित में किसानों का बिजली के बिल के डिफाल्टर चार्ज में 10 से 75 प्रतिशत की छूट दी गई है।

बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी रहा फोकस

28422 मेगावाट पूर्व प्रदेश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता

6000 मेगावाट बिजली सरकार ने जोड़ा

आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के साथ साथ सरकार ने प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है। प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 28422 मेगावाट हो गई है। यह पूर्वांचल सरकार के मुख्यमंत्री 6000 मेगावाट जोड़ा है।

8262 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं

इनमें से कई परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं और जल्द ही इनसे उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। पारंपरिक स्रोतों के अलावा सरकार ने गैर पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने नई नीति जारी नीति की घोषणा की है। 100 मेगा के अलावा 25.00 मेगावाट क्षमता की सरकार के 10.00 मेगावाट के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन 2000 मेगावाट तक पहुंच गया है।

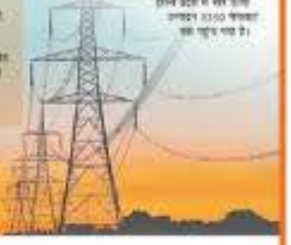

नारी शक्ति का सम्मान

लखनऊ

लखनऊ। योगी सरकार महान के दौरान प्रदेश सरकार ने नारी की सुरक्षा और सम्मान की बराबर रक्षाने की दिशा में कई सकारात्मक प्रयास हुए हैं। इस संकल्पने की सबसे पहले बेटियों की सुरक्षा के लिए 'ऐंटी रोमियो स्क्वायड' का गठन करवाए सरकार ने यहां बेटियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ पर रोक लगाई, यही प्रदेश के सभी 1111 थानों पर महिला हेल्प डेस्क और महिला बीट अधिकारियों की नियुक्ति करके उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इसके अलावा महिलाओं को स्वयं स्वरोजगार दिलाने के लिए 2.16 करोड़ रुपए देकर बीटें भी 31 महिलाएं संचालित स्वयंसहायता ग्रुप बनाए गए स्वयंसहायता की गई स्थापना की गई।

सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के प्रति के लोगों को जागरूक करने के लिए 'मिशन शक्ति' अभियान शुरू कर एक नया प्रयोग किया, जो काफी सफल रहा है। जहां और पुरुषों साथ का अभियान स्वयंसहायता की सुरक्षा के और सेवाएं चलाया जाता रहा है। मिशन शक्ति अभियान के साथ अब तक 8.5 करोड़ महिलाओं को आगे आकर और कार्यों के प्रति जागरूक किया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही उनको शिक्षा, रोजगार और सेहतमंद बनाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं को समाज तक की सुरक्षा किया की सुरक्षा के लिए 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत 'एंटी रोमियो स्क्वाड' का गठन करवाया गया। यह बेटियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ पर रोक लगाई, यही प्रदेश के सभी 1111 थानों पर महिला हेल्प डेस्क और महिला बीट अधिकारियों की नियुक्ति करके उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इसके अलावा महिलाओं को स्वयं स्वरोजगार दिलाने के लिए 2.16 करोड़ रुपए देकर बीटें भी 31 महिलाएं संचालित स्वयंसहायता ग्रुप बनाए गए स्वयंसहायता की गई।

'ऐंटी रोमियो स्क्वायड' का असर

40 लाख महिलाओं को जिला स्तर, प्रखंडस्तरीय स्वयं सहायता योजना के तहत

10.01 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभान्वित किया गया था।

1.52 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार की ओर दिए जाने वाले 35 हजार रुपये की अनुदान राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया।

माफिया पर वार से कानून व्यवस्था में हुआ सुधार

अपराधियों में पुलिस का डर, उपद्रवियों को अब है संपत्ति जब्त होने का खौफ

1866 करोड़ रुपये की भूमाफिया की संपत्ति जब्त

लखनऊ। योगी सरकार चार साल से प्रदेश में कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार लेकर आई है। एक ओर जहां पुलिस का इकबाल बढ़ा है वहीं महिला और अपराधियों में पुलिस कानून का खौफ भी बढ़ा है। महिलाओं के प्रति अभिव्यक्ति के अंतिम छोर में मौजूदगी जब कानून, माफियों संपत्ति की जब्तीकरण कार्यवाही सहूलियत करना और अपराध व अपराधियों के खात्मे के लिए सरकार की ओर से तीनों तीनों कार्यों कारण शामिल हुई है।

सरकारने अपराधों को खत्म तो वहीं चार साल में प्रदेश के माफियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 1866 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। 2296 के मुकाबले 2020 में अपराध के आंकड़ों में भारी गिरावट आई है। डकैती की घटनाओं में 70 प्रतिशत, लूट की घटनाओं में 60 प्रतिशत, हत्या की घटनाओं में 29 प्रतिशत, बलात्कार की घटनाओं में 33 प्रतिशत, छेड़ छेड़खानी में 100 प्रतिशत, अपहरण की घटनाओं में 33 प्रतिशत, दंगे की घटनाओं में 11.6 प्रतिशत और दुष्कर्म के मामलों में 12 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं गत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का सबसे है तो पुलिस के साथ मुठभेड़ में 150 अपराधी मारे गए हैं। 3423 अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। सिर्फ इसी में 44,139 अपराधियों गिरफ्तार किए गए और 630 अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की गई है। इनमें से वहीं 13564 इनामी अपराधियों को गिरफ्तारी की गई है। वहीं 2019 में गन्नाकिसान संगठन अभियान के विरोध में प्रदर्शन करने वाले और मोटरवाहनों को क्षतिग्रस्त पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जबकि वर्ष पांचवीं पर रेल के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे विकास कार्य कार्यालय लखनऊ द्वारा प्रदेश रेलवे विकास निगमलक लखनऊ द्वारा 74 प्रतिशत पुलिस कर्मियों को पदोन्नति दिया गया।

जबरन धर्म परिवर्तन रोकने को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक लागू

चार शहरों में नातू की गई पुलिस आयुक्त प्रणाली

लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई। यहां लखनऊ और गोरखपुर में और उसकी संचालन का रेंजों पुलिस महानिदेश और महानुप में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई। यह भी इसके संचालनार्थ पुलिस रेंजों को किया गया है।

साढ़े चार साल में बने 214 नए थाने

प्रदेश में साढ़े चार साल में बाहरी सरकार और नीति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 214 नए थाने बनाए गए। सोमवारों को संचालन में पुलिस चौकियों खोली गई और इन चौकियों पर थाना घोषित कराया गया। इसके अलावा 1 रेंज में 1 जिले में 1 पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया। इसके अलावा 10 नए थाने भी खोले गए। 1 जिले में 1 पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया। इसके अलावा 10 नए थाने भी खोले गए। 1 जिले में 1 पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया। इसके अलावा 10 नए थाने भी खोले गए।

पुलिस का ढांचा सुधारने के लिए भी हुए काम

अपने चार साल की कार्यावधि में प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के ढांचे को सुदृढ़ किया है। सरकार का अधिकतम प्रयास है कि प्रदेश के अनुसार लोक सेवाएं पुलिस और पीसी पीएसी सशस्त्र बल गठन किया गया। पूरी 112 एक ही सहित पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई और इस एक साल में लगभग पांच चौकियों को नया बनाने या उन्नत बनाने पर जोर रहा। पुलिस में लगातार भी। योगी की सुरक्षाओं से इसके लिए एसएसबी कमांडोज बल एवं की एसएसबीएस कमांडो गठन। जहां इस प्रदेश की बात है, पुलिस कर्मियों के घरों के लिए बैरक, पुलिस लाइन और कार्यालय का निर्माण कार्य किया गया है। सरकार ने पुलिस कर्मियों उत्तर प्रदेशपुर का गठन किया गया है।

- महिला सुरक्षा एवं बाल सुरक्षा संगठन, राष्ट्रीयसंगठन और संगठन विभागीयों योजना का गठन किया गया है। महाकुंभ लखनऊ के संचालन के लिए रेंज स्तर पर अलग पोस्टिंग गई हैं। महाकुंभ में पर्याप्त पुलिसबल प्रदेश रखा गया है। इसके अलावा 1 जिले में 1 पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया। इसके अलावा 10 नए थाने भी खोले गए हैं। इस साल में प्रदेश में लगभग 30 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई और 16 हजार पुलिस कर्मियों की पदोन्नति किया गया।

10 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना

लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और झांसी प्रदेश 10 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना किया जा रहा है। आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी पर है। मेरठ और गोरखपुर की सीनियर मेट्रो कनेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है।

लखनऊ, इलाहाबाद और झांसी में जल्द ही लाइट मेट्रो तुरन्त प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। लखनऊ में उत्तरी भाग में 'लखनऊ के अवधपुरम तक' 11.165 किमी, मेट्रो रेल मार्ग के निर्माण के लिए कार्यवाही प्रगति पर है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के 32.4 किमी, तीन कॉरिडोर का निर्माण तेजी पर है।

अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे का विकास गतिमान

वर्ष 2017 में प्रदेश में कम 2 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी में विस्तारीकरण के कार्यान्वयन के अलावा, कानपुर, गोरखपुर, बिरसा, आगरा एवं कांगड़ा हवाई अड्डों संचालित हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों विकसित हैं। गोरखपुरहवाई के बेस में लखनऊ-आजमगढ़ हेलीकॉप्टर सेवाएं हवाई अड्डे के विकास की प्रक्रिया चलाया है। आजमगढ़ पूर्वी जिलेहवाई हैं। अयोध्या में भी अयोध्या पुनर्विकास प्रदेश हवाई अड्डे का विकास चलिया है। 12 अन्य छोटे-छोटे हवाई पट्टों का कार्य प्रगति पर है। इसमें अलीगढ़, आजमगढ़, बहराइच, कुशीनगर, चित्रकूट और मोरादाबाद (संभल) एयरपोर्ट पूर्ण होने की दिशा में हैं। इस वर्ष में प्रदेश में जारी हैं 30 एयरपोर्ट कार्यालय होंगे। प्रदेशभर कानपुर में भी 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में आया। इस वर्ष एक साथ 43 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई और 16 हजार पुलिस कर्मियों की पदोन्नति किया गया।

बेघरों को दिलाया घर

42 लाख से अधिक पीएम आवास बन चुके

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.8 लाख आवास का भी निर्माण पूरा

लखनऊ। हर बेघर को घर, शहरी क्षेत्रों में विकास और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादन स्थल अपने कार्य संकल्पों को प्रदेश सरकार ने पूरा किया है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (शहरी) के तहत लोगों को आवास देने का काम किया गया है। यहां इस योजना के तहत बीते साढ़े चार साल में अब तक करीब 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हो चुका है। यहीं मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत भी 1.8 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

इसी प्रकार मुरादाबाद, गाजियाबाद और कुछ ऐसे के प्रमुखित परिवारों को मकानों को दो घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जा चुकी है। इसके लिए यूपी 32642 प्रकार बनाए गए। इसके ही यहीं बाहरियों गांवों को भी हजार गांव का हो चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.8 लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए हो चुके कोरी मुख्यमंत्री जनी आवासन।

और सीतापुर जैसे मुख्यमंत्री जनी कार्य पूरा। यहीं इस बार की आवासीय सहायता को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए प्रति यूपी 32642 प्रकार बनाए गए। इसके ही यहीं बाहरियों गांवों को भी हजार गांव का हो चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.8 लाख आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

स्मार्ट सिटी से सुधरी शहरों की तस्वीर

प्रदेश के शहरों के विकास पर पहली बार योजना किया गया। केन्द्र और राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने सुविधा सुलभ बनाने के लिए 'स्मार्ट सिटी मिशन' की शुरुआत की है। केन्द्र ने यहां 12 स्मार्ट लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, झांसी व आजमगढ़ को 'स्मार्ट सिटी' के तौर पर चिन्हित करने की योजनाओं पूरा करने के लिए 60 करोड़ से बनाया और योजना को सुविधा सुलभ कराई गई है।

प्रदेश के सभी 75 जिले हो चुके ओडीएफ

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में चलाए गए प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों को ओडीएफ घोषित कर दिया है। यह भी एक महान सफल है जहां। इस मिशन के तहत प्रदेश के सभी शहरों के 100 तक 60 हजार, 240 सामुदायिक शौचालय एवं 602 सिंक शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यूपी प्रदेश में 2417 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है।

बजट अभियान भी रहा कारगर

पेयजल, सीवरेज व नगरिकों के व्यवहारगत को बदलना के 'सुख' यह नागरिकों को बड़ी सहूलियत देने हुए सरकार द्वारा सुख किया गया 'बजट अभियान' चलाई जाएगा।

13,52,290 बजटों का अब तक 20 अभियान के बाद सरकारने किया गया। इसमें अब तक की सर्वाधिक और करीब 82 फीसदी लोगों ने सुविधा लिए गए।

हर खेत को पानी, हर घर को शुद्ध पेयजल

1.49 लाख किलोमीटर से अधिक नहरों की सिल्ट सफाई

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार सरकारी ने खेत खेत भाग सहार ने उत्तर प्रदेश में किसानों को नई उम्मीदें दिखाई है। इस कार्यक्रमों के हर खेत को पानी और हर घर को जल का सपना साकार हुआ। प्रदेश में 2021 किसानों में 14.21 लाख कनेक्शन राज्य को यह। हर घर जल योजना के तहत 50 हजार ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई गई है।

हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 46 नहरों के

राष्ट्रीय जल जीवन मिशनकेस राष्ट्रीय पेयजल योजना, बोरवेल योजना, जलजीवन योजना, पेयजल योजना, नलकूप योजना, पुल योजना, सीवर जल योजनाओं के जलकनेक्शन राज्य प्रदान की गई। 4.24 लाख के अधिक नियमुक्त बोरिंग, 4023 नहरी योजना, 13194 सरकार नहरी योजना के भी निर्माण की सफल को बढ़ाया गया है। दो हजार तक राजकीय नलकूपों का निर्माण, 787 सहकारी नलकूपों का मुख्यमंत्री निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्माण कार्य 1148 कार्यों कार्य का सफलता किया गया, जो अपने आप में एक मिसाल है।

योगी सरकार ने 1.49 लाख किलोमीटर से अधिक नहरों की सिल्ट सफाई की है। 4.24 लाख के अधिक नियमुक्त बोरिंग, 4023 नहरी योजना, 13194 सरकार नहरी योजना के भी निर्माण की सफल को बढ़ाया गया है। दो हजार तक राजकीय नलकूपों का निर्माण, 787 सहकारी नलकूपों का मुख्यमंत्री निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्माण कार्य 1148 कार्यों कार्य का सफलता किया गया, जो अपने आप में एक मिसाल है।

गंगा हुई निर्मल, सभी जिले ओडीएफ

नमामि गंगे को 22 परियोजनाएं पूरी

गंगा को निर्मल बनाने के लिए यूपी की नई नमामि गंगे परियोजना के तहत की प्रदेश में पूरा कर लिया गया है। किसानों के लिए बोरिंग तक बनाया गया सकीय गंगे के लिए मोहल्ला बनाने परियोजनाओं में के अब तक 22 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केन्द्र और प्रदेश सरकार के सहयोग प्रयास से अमृत योजना के तहत प्रदेश के 60 शहरों में सेवाएं और परियोजना को सुविधा सुलभ कराई गई है।

90 लाख लोगों को योगी सरकार दे रही पेंशन

हर बुजुर्ग, दिव्यांगजन, विधवा और निराश्रित महिला को मदद देने का लक्ष्य सर्वजन उदय के भाव बढ़ रही सरकार, बुजुर्गों के लिए अलग होम प्रोजेक्ट

कमल कर्मी

लखनऊ। योगी सरकार महाकाल में 90 लाख से अधिक पात्र लोगों को पेंशन दे रही है। प्रदेशभर उत्तर केन्द्रीय सरकार हर बुजुर्ग, दिव्यांगजन, विधवा और निराश्रित महिला को पेंशन देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। बुजुर्गों की पेंशनकार के लिए प्रदेश के हर जिले में वरिष्ठ होम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।

इस अभियान की शुरुआत इसकारणों योगी योगी की कर चुके हैं। प्रदेश में आत्मनिर्भर बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्यों, विकास पर जोर, बुजुर्गों, दिव्यांगजन, विधवा और निराश्रित महिला को पेंशन देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। बुजुर्गों की पेंशनकार के लिए प्रदेश के हर जिले में वरिष्ठ होम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।

इस अभियान की शुरुआत इसकारणों योगी योगी की कर चुके हैं। प्रदेश में आत्मनिर्भर बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्यों, विकास पर जोर, बुजुर्गों, दिव्यांगजन, विधवा और निराश्रित महिला को पेंशन देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। बुजुर्गों की पेंशनकार के लिए प्रदेश के हर जिले में वरिष्ठ होम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।

- दिव्यांगजन पेंशन की राशि बढ़ा 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की गई। 11 लाख 16 हजार 300 दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ दिया गया है। 1 लाख 77 हजार 971 सहायिक मंत्र से लक्ष्य महिलाओं को सुविधा और और सहायक उपकरण वितरित किए गए। मुख्य दिव्यांगजनों के मुख्यमंत्री के लिए 2500 रुपये और बढ़ाकर की गई। 2121 दिव्यांगों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान दिया गया है। मुख्य के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये और मुख्यमंत्री के दिव्यांग होने पर 30 हजार रुपये और दोनों के दिव्यांग होने पर 30 हजार रुपये विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ दिया जाता है।

1.79 करोड़ प्रदेश-प्रवासियों को दी गई 13620 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन

- दिव्यांगजन पेंशन की राशि बढ़ा 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की गई। 11 लाख 16 हजार 300 दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ दिया गया है। 1 लाख 77 हजार 971 सहायिक मंत्र से लक्ष्य महिलाओं को सुविधा और और सहायक उपकरण वितरित किए गए। मुख्य दिव्यांगजनों के मुख्यमंत्री के लिए 2500 रुपये और बढ़ाकर की गई। 2121 दिव्यांगों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान दिया गया है। मुख्य के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये और मुख्यमंत्री के दिव्यांग होने पर 30 हजार रुपये और दोनों के दिव्यांग होने पर 30 हजार रुपये विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ दिया जाता है।

वृद्धावस्था पेंशन प्रतिमाह 400 से बढ़ाकर 500 रुपये

55.77 लाख वृद्धजन इसका लाभार्थी

लखनऊ। वृद्ध जनों अपने बुजुर्गों पेंशन प्रतिमाह 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की। लगभग 55 लाख 77 हजार वृद्धजन इसके लाभार्थी हो रहे हैं।

निर्माण श्रमिकों की पूर्ण के विवाह पर अब 75 हजार रुपये तक अनुदान

- सरकार मंत्रमुक्त निर्माण श्रमिकों की पुत्री के विवाह के लिए 35 हजार रुपये तक का अनुदान देती है। योजना के अब तक 20151 पुत्रियों लाभान्वित के पुत्री हैं। अगस्त पिछले योजना में 36 लाख 60 हजार 413 पुत्रियों का लाभ मिला है। इसी तरह उत्तरप्रदेश का 6 लाख 20 हजार 313 लोग लाभान्वित हैं।
- प्रदेश में बाहरी, राजी, योजनी मुहाना, लाई, मुहाना, मोहान, मुहाना, बलवाई आदि के योजनाओं के लिए विभागवार अब सरकार योजना और उसका प्रदेश भारी बाहर का काम हुआ है। 1.25 करोड़ परिवारों उत्तरप्रदेश राजकीय योजना पहुंचे विस्तारण योजनाओं हैं। इसका ही यही अनुसूचित जाति व जनजाति आयोगका विकास अधिनियम 1989 के अधीन कार्य कलापों के लाभार्थियों के लिए 25 पद बढ़ाए गए हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में एकमुश्त 30 हजार रुपये सहायता

सरकार राज्य के कर्मचारी में पुरुषों पारिवारिक लाभ योजना के 1 लाख 74 हजार 602 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। इस योजना के तहत पारिवार के कमाऊ पुरुष का निधन होने पर परिवार को एकमुश्त 30 हजार रुपए सहायता दी जाती है। 1 लाख 77 हजार 971 सहायिक मंत्र से लक्ष्य महिलाओं को सुविधा और और सहायक उपकरण वितरित किए गए। मुख्य दिव्यांगजनों के मुख्यमंत्री के लिए 2500 रुपये और बढ़ाकर की गई। 2121 दिव्यांगों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान दिया गया है। मुख्य के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये और मुख्यमंत्री के दिव्यांग होने पर 30 हजार रुपये और दोनों के दिव्यांग होने पर 30 हजार रुपये विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ दिया जाता है।

कन्याशिक्षा, सुरक्षा, बीमा और सात सरकारी के 20 लाख राज्यस्तर तक पेंशन दी गई 27164 सुरक्षा और 4000 सरकारीकार और 81 लाख सरकारीकार के लाभ और ग्रेड अलग सरकारीकार के लिए अलग सरकारीकार दिए गए।

शेष पेज लखनऊ-8 में देखिए